

## सिविल विविध

समक्ष:बी. आर. तुली और ए. एस. बैस जे.

काहना राम, फुला राम के बेटे और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

लता सिंह और अन्य - उत्तरदाता।

1968 की सिविल रिट संख्या 3712 और

1971 का सिविल विविध संख्या 3111

7 नवंबर, 1974

पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम (1949 का XXXVIII) - धारा 5, 6, 7 और 14- अधिनियम के तहत 20 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि - भूमि मालिक - क्या पट्टेदार की चूक के लिए पट्टे के निर्धारण के लिए कलेक्टर को आवेदन करने का अधिकार है - कलेक्टर द्वारा ऐसे आवेदन की अस्वीकृति - क्या झूठ है - कलेक्टर द्वारा निर्धारित भूमि का पट्टा - ऐसी भूमि - क्या बहाल की जा सकती है। धारा 7 में "या इसकी पूर्व समाप्ति" शब्दों की कमी के बावजूद 20 वर्षों की समाप्ति से पहले भूमि मालिक ।

ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट, 1949 की धारा 5, 6 और 7 के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिन भूस्वामियों की भूमि को अधिनियम के तहत पट्टे पर दिया गया है, उन्हें 20 साल की लीज की अवधि समाप्त होने से पहले उन्हें भूमि की बहाली के लिए कहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन कलेक्टर को ऐसी समाप्ति से पहले ही भूस्वामियों को पट्टे की भूमि का कब्जा बहाल करने पर कोई रोक नहीं है, यदि वह उचित समझता है, मामले की परिस्थितियों में, अर्थात्, यदि पट्टेदार भूमि को छोड़ देता है या कलेक्टर द्वारा पट्टे की शर्तों को पूरा करने में उसके द्वारा की गई चूक के कारण या किसी अन्य कारण से उसका पट्टा समाप्त कर दिया जाता है, भूमि किसी भी पट्टेदार की किरायेदारी के अधीन नहीं है। इसलिए, यह है। भू-स्वामी को कलेक्टर के ध्यान में लाने के लिए खुला है कि एक निश्चित पट्टेदार ने पट्टे की शर्तों को पूरा करने में चूक की है, जो कलेक्टर को उस पट्टे को निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसके बाद कलेक्टर को मामले की जांच करनी है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर पट्टे का निर्धारण करना है या नहीं। इसलिए भूस्वामी को कलेक्टर को आवेदन देने का अधिकार है कि वह इस तथ्य को उनके ध्यान में लाए कि उनकी भूमि के पट्टेदार ने अपने पट्टे की शर्तों को पूरा करने में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप पट्टे का निर्धारण किया जा सकता है। वास्तव में, भूमि में कोई भी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर को ऐसा आवेदन दे सकता है।

ये अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 14 में प्रयुक्त "पीड़ित व्यक्ति" शब्द के कई अर्थ हैं और इस मामले को प्रत्येक मामले में तय किया जाना है कि क्या कोई व्यक्ति, जो अपील दायर करने का दावा करता है, वह 'पीड़ित व्यक्ति' है या नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी निश्चित

मामले में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार दिया जाता है और उसका विवाद नकारात्मक होता है, तो वह निश्चित रूप से उसके विवाद को अस्वीकार करने वाले आदेश से व्यथित होता है। जहां जिन भूस्वामियों की भूमि अधिनियम के तहत पट्टे पर दी गई है, उन्हें कलेक्टर को यह सूचित करने का अधिकार है कि पट्टेदारों ने पट्टे की शर्तों को पूरा करने में चूक की है जिसके परिणामस्वरूप उनके पक्ष में पट्टे का निर्धारण किया जाना चाहिए और यदि कलेक्टर द्वारा उनके उस विवाद को अस्वीकार कर दिया गया है, वे स्वाभाविक रूप से "पीड़ित व्यक्ति" हैं और उन्हें कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है जो पट्टे का निर्धारण करने से इनकार करते हैं।

ये अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 7 में "पट्टे की समाप्ति पर" शब्द उस चरण को दर्शाता है जब भूमि किसी भी व्यक्ति की किरायेदारी के अधीन नहीं रहती है। चाहे पट्टे की समाप्ति द्वारा या पट्टेदार द्वारा परित्याग करके या किसी अन्य तरीके से। जब पट्टेदार द्वारा किए गए डिफॉल्ट के कारण पट्टा पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारित किया जाता है, तो यह समाप्त हो जाता है और समाप्त हो जाता है। इसके बाद, कलेक्टर द्वारा किसी और के पक्ष में एक और पट्टा बनाया जा सकता है, यदि वह ऐसा सोचता है या वह भूमि मालिक को बहाल कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि वह उसी पर खेती करने की स्थिति में है। अतः अधिनियम की धारा 7 से "या इसकी पूर्व समाप्ति" शब्दों को केवल हटाने का मतलब यह नहीं है कि भूस्वामी को कलेक्टर से उसकी बहाली के लिए प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है।

20 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले भूमि, भले ही पट्टेदार के पक्ष में पट्टा कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा की गई चूक होती है।

*माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजीत सिंह सरकारिया द्वारा दिनांक 17 फरवरी,-- 1971 के आदेश के माध्यम से इस मामले में शामिल कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया गया। डिवीजन बेंच में माननीय न्यायमूर्ति बाल राज तुली और माननीय न्यायमूर्ति अजीत सिंह बैस शामिल थे। संदर्भित कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश, — 11 नवंबर, 1974 के आदेश के तहत लौटा दिया गया।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि सर्टिओररी की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो न्यायाधीश द्वारा पारित 28 नवंबर, 1968 (अनुबंध 'डी' में निहित) आदेश द्वारा पारित किया गया है। 1974.

सी.एम. 3111 का 1971.

.....

आदेश 6, नियम 17 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद संख्या 12 में निम्नलिखित याचिका जोड़कर रिट, याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाए। 7 ग्राउंड नंबर 8 के रूप में।

*"(viii) कि ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट की धारा 6 उत्तरी भारत कैटर्स*

मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। आई.आर. 1967 सुप्रीम कोर्ट 1581 कलेक्टर के रूप में या तो इस धारा के तहत आगे बढ़ने या पट्टेदारों के निष्कासन के लिए राजस्व अदालत में नियमित तरीके से आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है। हरियाणा राज्य द्वारा अधिनियम सं 2008 द्वारा किया गया संशोधन। 1969 की धारा 33 में पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1959 ने अपने उद्देश्य को हासिल नहीं किया है और उक्त धारा 6 अभी भी अधिकार क्षेत्र से बाहर है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एन. एल. ढींगरा।

एम. एम. पुंछी, एडवोकेट, (सुरेश अम्बा, एडवोकेट, उनके साथ), उत्तरदाताओं 1 से 3 के लिए ।

सी. डी. दीवाना अतिरिक्त महाधिवक्ता। हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए 4 से 6।

## आदेश

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था :-

तुली, जे- 1968 की ये रिट याचिकाएं संख्या 3712 (काहना राम और अन्य बनाम लता सिंह और अन्य, 1968 के 3757 (किशन सिंह और अन्य बनाम प्रीतम सिंह और अन्य, 1968 के 3758 (संत सिंह और अन्य बनाम गुरबख्श सिंह उर्फ गुरबचन सिंह और अन्य, 1969 की धारा 425 (वरयाम सिंह और एक अन्य वी। भारपुर सिंह और अन्य, 1969 की धारा 427 (श्रीमती ईश्वरी और अन्य बनाम चूहर सिंह और अन्य) और 1969 की धारा 428 (देवा सिंह और एक अन्य बनाम चांद सिंह और अन्य) समय-समय पर यथासंशोधित पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 की धारा 6 और 7 के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा 6 के अंतर्गत आवेदन करने की भूस्वामी की योग्यता को शामिल किया गया है और परिणाम उसके विरुद्ध जाने की स्थिति में है। 17 फरवरी, 1971 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए संदर्भ के आदेश के अनुसरण में इस तरह के आवेदन और अपील पर निर्णय लेने के लिए धारा 14 और कलेक्टर और आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के तहत अपील को प्राथमिकता देना। बिंदु तय करने के लिए, 1968 के सीडब्ल्यू 3712 के तथ्यों को बताया जा सकता है।

(2) प्रतिवादी 1, 2 और 3 से संबंधित बंजार कादिम और बिना खेती वाली 105 एकड़ भूमि को पंजाब राज्य द्वारा 1958 में शेखू खेड़ा, तहसील सिरसा, जिला हिसार की राजस्व संपदा में अधिनियम के तहत कलेक्टर, हिसार के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, और 4 अगस्त को 20 वर्षों की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं को पट्टे पर दिया गया था। 1958. कलेक्टर और याचिकाकर्ताओं के बीच लीज-डीड तैयार किया गया था जिसमें निर्धारित किराया 2.50 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष था। पट्टे की शर्तों के तहत, पट्टेदारों को छह महीने की अवधि के भीतर आधी भूमि को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी और शेष आधे को पट्टे की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनः प्राप्त करना था। भूमि घग्गर नदी द्वारा बाढ़ आ जाती थी, और 15 फरवरी, 1959 को, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर को एक आवेदन दिया कि **भूमि, पानी के नीचे** होने के कारण, पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है और परिणामस्वरूप, उन्हें कुछ अन्य भूमि दी जा सकती है। उस आवेदन पर, तहसीलदार ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि सरकार नदी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नदी के दोनों किनारों पर घग्गर बैराज और बांध का निर्माण कर रही है। नदी को नियंत्रित करने का काम 1963 में पूरा हुआ और उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने भूमि को पुनः प्राप्त किया और अक्टूबर और नवंबर, 1963 में रबी फसल के साथ इसे बोया। यहन-

फसल अप्रैल, 1964 में परिपक्व होनी थी, और 16 दिसंबर, 1963 को, भूस्वामियों, यानी प्रतिवादी 1, 2 और 3 ने कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता, पट्टेदार के रूप में, निर्धारित अवधि के भीतर भूमि पर खेती करने में विफल रहे थे और परिणामस्वरूप उनके पट्टे समाप्त किए जाने योग्य थे। उन पट्टों

को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की गई थी। कलेक्टर ने उन आवेदनों को तहसीलदार सिरसा को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भेज दिया, बाद में, याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी किए बिना, इस आशय की एक पक्षीय रिपोर्ट बनाई कि भूमि अभी भी बंजार कादिवी थी और तब तक इसे तोड़ा नहीं गया था। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कलेक्टर ने पंजाब भूमि उपयोग नियम, 1950 के नियम 5 का अनुपालन किए बिना, कलेक्टर, हिसार को आदेशों के लिए निम्नलिखित नोट प्रस्तुत किया: -

"नीचे दिए गए छह आवेदन (मार्जिन में दिए गए विवरण) सिरसा के तहसील सिरसा के शेखू खेड़ा गांव के भूस्वामियों से इस आधार पर अपनी जमीन जारी करने के लिए दिए गए हैं कि जिन पट्टेदारों को पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम के तहत 20 साल के लिए पट्टे पर भूमि आवंटित की गई थी, वे न तो गांव में बस गए हैं और न ही भूमि को खेती के तहत लाए हैं। ये सभी अनुप्रयोग समान प्रकृति के हैं और उनके तथ्य समान हैं।

इस मामले में तहसीलदार सिरसा के माध्यम से की गई जांच से पता चला कि आवेदनों में निहित तथ्य सही हैं। फाइल पर रखी गई खसरा गिरदावरी की प्रतियों से भी साफ पता चलता है कि घटनास्थल पर बंजार की जमीन पड़ी है। यह स्पष्ट है कि पट्टेदारों ने छह साल से अधिक की अवधि के लिए भूमि को पुनः प्राप्त नहीं करके पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है और इन कारणों से उनके पट्टे रद्द होने की संभावना है।

उपमंडल अधिकारी, सिरसा। पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं, और हम कर सकते हैं। इसलिए, उनसे अनुरोध है कि इस भूमि का उपयोग कुछ अन्य वास्तविक भूमिहीन हरिजनों को पट्टे पर आवंटन के लिए करें, बशर्ते वह मौके पर बंजार पड़ी हो, लेकिन अगर इसे भूस्वामियों द्वारा खेती के तहत लाया गया है, तो इसे उनके पक्ष में जारी किया जा सकता है।"

हिसार के कलेक्टर ने 22 फरवरी को निम्नलिखित आदेशों को पारित किया। 1964. उपर्युक्त कार्यालय नोट पर:-

"उन्होंने कहा, 'मैं प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत हूं। उप-विभागीय अधिकारी को आगे स्पष्ट रूप से सलाह दी जानी चाहिए कि वे स्वयं को संतुष्ट करें।



जमीन जारी करने से पहले पूरी तरह से क्योंकि अनुभव से पता चलता है कि आम तौर पर मालिक अनुचित लाभ पाने के लिए ऐसे मामलों में गलत रिपोर्ट बनाते हैं।”

इसके बाद कलेक्टर के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए कागजात सिरसा के उप-मंडल अधिकारी श्री जीएल नागपाल को भेजे गए। श्री नागपाल ने 15 मार्च, 1964 को गांव का दौरा किया और याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद बताया कि भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। तब याचिकाकर्ताओं को पता चला कि उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही चल रही है और उन्होंने 24 मार्च, 1964 को कलेक्टर के 22 फरवरी, 1964 के आदेश को रद्द करने के लिए समीक्षा आवेदन किया। कलेक्टर ने महसूस किया कि वह आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने पिछले आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते। 7 जून, 1966 को आवश्यक अनुमति प्रदान की गई और फिर मामले की जांच श्री राम एस वर्मा, आई.ए.एस., उप-विभागीय अधिकारी, कलेक्टर, सिरसा की शक्तियों के साथ की गई, जिन्होंने पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद 17 अप्रैल, 1967 को एक विस्तृत आदेश पारित किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रबी, 1964 से पहले भूमि को खेती के तहत नहीं लाया गया था, लेकिन पट्टे का निर्धारण करना उनके लिए अनिवार्य नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने संतोषजनक रूप से साबित कर दिया था कि घग्गर बांध में बाढ़ के कारण 1963 से पहले भूमि को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था और जिस क्षण राज्य सरकार ने घग्गर बांध का निर्माण किया था। भूमि का पुनर्ग्रहण हाथ में लिया गया था। उत्तरदाता 1 से 3 के आवेदन तब खारिज कर दिए गए थे। अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ, उक्त प्रतिवादियों ने अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील दायर की, जिसे आयुक्त, अंबाला डिवीजन ने 17 अक्टूबर, 1968 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। उस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण को वित्तीय आयुक्त ने 28 नवंबर, 1968 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने तब वर्तमान याचिका दायर की।

अधिनियम की योजना पर अब विचार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 के तहत, कलेक्टर भूस्वामियों को नोटिस जारी करने के बाद किसी भी भूमि का कब्जा ले सकता है जिस पर छह या अधिक फसल के लिए खेती नहीं की गई है। मुआवजे का भुगतान अधिनियम की धारा 4 के तहत भूस्वामियों को किया जाना है और अधिनियम की धारा 5 के तहत, कलेक्टर उस भूमि को कम से कम 7 साल या 20 साल से अधिक के लिए पट्टे पर दे सकता है। धारा 6\* कलेक्टर को पट्टे का निर्धारण करने की शक्ति देती है जहां पट्टेदार अपनी शर्तों का उल्लंघन करता है और धारा 7 के तहत भूमि का कब्जा समाप्त होने के बाद भूस्वामी को बहाल किया जाना है।





पट्टा। यह लीलू और अन्य बनाम करम चंद और अन्य, (आई.एल.आर. (1965) 1)(1) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, कि :-

“\* \* \* कलेक्टर का कब्जा बरकरार रख सकता है

भूमि 20 वर्षों के लिए और इस अवधि के दौरान भूमि के पट्टे को प्रभावी करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 7 वर्ष से कम हो और कोई भी पट्टा भूमि के कब्जे के मूल लेने की तारीख से 20 वर्ष से अधिक न हो। इस शक्ति का उपयोग या तो मूल पट्टे की मुद्रा के दौरान या इसकी समाप्ति पर किया जा सकता है, बशर्ते, निश्चित रूप से, भूमि का कब्जा लेने की तारीख से 20 साल की अधिकतम अवधि पार न हो। (हेड-नोट के अनुसार)।

कमल को-ऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी लिमिटेड, पिहोवा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (1972 पी.एल.जे. 172)(2) में इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ अभिनिर्धारित किया गया था, कि :-

"धारा 6 और 7 के नंगे पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि धारा 6 उन प्रकार के मामलों से संबंधित है जहां पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले कलेक्टर द्वारा पट्टे को रोक दिया जाता है, जबकि धारा 7 में उन मामलों की परिकल्पना की गई है जहां पट्टे की अवधि समाप्त होने पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है। धारा 7, जैसा कि इसके सादे पठन से स्पष्ट है, उस संपत्ति के मालिकों को कब्जा देने के लिए एक विधि प्रदान करता है जिससे वे अधिनियम की धारा 3 के तहत वंचित थे। पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद, पट्टेदार में कोई अधिकार नहीं बचता है जो अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे प्राप्त करता है। पट्टेदार के विरुद्ध साधारण न्यायालय में कार्यवाही करने का प्रश्न शायद ही उठता है, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद कलेक्टर के कहने पर पट्टेदार पट्टे की भूमि का कब्जा वापस करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विधायिका ने अपने ज्ञान में निष्कासन की यह सारांश विधि प्रदान की। यदि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील को सही माना जाता है, तो अधिनियम का पूरा उद्देश्य निराश हो जाएगा। धारा 7 की उपधारा (1) केवल यह कहती है कि यदि कलेक्टर द्वारा उप-धारा (3) के तहत जिस भूमि का कब्जा लिया गया है और पट्टे की समाप्ति पर मालिक को वापस किया जाना है, तो कलेक्टर, ऐसी जांच करने के बाद, जैसा कि वह मानता है आवश्यक, लिखित रूप में आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें कि भूमि का कब्जा किस व्यक्ति को दिया जाना है। कलेक्टर द्वारा की जाने वाली जांच केवल उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए होती है जिसे धारा 7 के तहत भूमि का कब्जा दिया जाना है। अधिनियम की योजना ऐसी है कि अधिनियम की धारा 7 के तहत आने वाले मामलों में निष्कासन स्वचालित रूप से होना चाहिए और पट्टेदार को अपने निष्कासन पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है और उसके पास भूमि खाली करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू होती है, तो पट्टेदार के लिए उपलब्ध एकमात्र आपत्ति यह है कि पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

उस फैसले की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने *दसौधा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*, (1973 पी.एल.जे.) (3), के मामले में की थी, जिसमें यह बताया गया था कि कलेक्टर केवल 20 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए मालिक से भूमि का कब्जा लेने का हकदार था, जिसके लिए वह इसे किरायेदार को पट्टे पर दे सकता था। पट्टे की समाप्ति के बाद, भूमि का कब्जा उसके मालिक को बहाल किया जाना है। उस व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए जिसे कब्जा बहाल किया जाना है, धारा 7 में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भूस्वामियों को 20 साल की समाप्ति से पहले उन्हें भूमि की बहाली के लिए कहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन कलेक्टर को उस अवधि की समाप्ति से पहले भी भूस्वामियों को कब्जा बहाल करने पर कोई रोक नहीं है, यदि वह उचित समझता है, तो मामले की परिस्थितियों में, अर्थात्, यदि पट्टेदार भूमि को छोड़ देता है या कलेक्टर द्वारा पट्टे की शर्तों को पूरा करने में उसके द्वारा की गई चूक के कारण उसका पट्टा समाप्त हो जाता है \* या किसी अन्य कारण से भूमि किसी पट्टेदार की किरायेदारी के अधीन नहीं रह जाती है। इसलिए, यह एक भूस्वामी के लिए खुला है कि वह कलेक्टर के ध्यान में यह लाए कि एक निश्चित पट्टेदार ने पट्टे की शर्तों को पूरा करने में चूक की है, जो कलेक्टर को उस पट्टे को निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसके बाद कलेक्टर को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर पट्टे की जांच करनी है और पट्टे का निर्धारण करना है या नहीं। इस प्रस्ताव पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एनएल ढींगरा ने भी सहमति व्यक्त की है। इसलिए, यह माना जाता है कि एक भूस्वामी को कलेक्टर को एक आवेदन देने का अधिकार है, जो इस तथ्य को उनके ध्यान में ला सकता है कि उसकी भूमि के एक पट्टेदार, जिसे कलेक्टर द्वारा अधिनियम के तहत पट्टा दिया गया था, ने अपने पट्टे की शर्तों को पूरा करने में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप

पट्टा निर्धारित किया जा सकता है। वास्तव में, भूमि में कोई भी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर को ऐसा आवेदन दे सकता है। इसलिए, इन मामलों में भूस्वामियों द्वारा कलेक्टर को किए गए आवेदन सक्षम थे।

निर्धारण के लिए दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या एक भूस्वामी, जिसका पट्टे का निर्धारण करने का अनुरोध, इस आधार पर कि पट्टेदार ने पट्टे की शर्तों को पूरा करने में चूक की थी, कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, को पीड़ित व्यक्ति कहा जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील दायर कर सकता है। न्यायिक निर्णयों में 'पीड़ित व्यक्ति' शब्दों को विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है। जेम्स, एल.जे., मामले में रे. *साइडबोथम* (1880), 14 सी.डी. 458 ने कहा: –

“पीठ ने कहा, 'लेकिन 'पीड़ित व्यक्ति' शब्द का वास्तव में मतलब यह नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस लाभ से निराश है जो उसे उस लाभ से निराश है जो उसे मिल सकता था अगर कोई अन्य आदेश दिया गया होता। एक 'पीड़ित व्यक्ति' एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने कानूनी शिकायत का सामना किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एक निर्णय सुनाया गया है जिसने उसे गलत तरीके से किसी चीज से वंचित कर दिया है, या गलत तरीके से उसे कुछ देने से इनकार कर दिया है, या गलत तरीके से उसके शीर्षक को प्रभावित किया है।”

जेम्स, एल.जे. द्वारा इस परिभाषा को लॉर्ड गोडार्ड, सी.जे. द्वारा आर. *बनाम लंदन सत्र अपील समिति, पूर्व भाग वेस्टमिनिस्टर सिटी काउंसिल* ((1951)1 ए.ई.आर. 1032.) (4) में सबसे अच्छी परिभाषा के रूप में वर्णित किया गया था ।

*रॉबिन्सन बनाम गुरी* ((1881), (7 Q.B.D. 465 C.A.: 470)(5), में ब्रैमवेल, एल.जे., ने कहा: –

“'पीड़ित व्यक्ति' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और इसे अधिनियमन के संदर्भ में माना जाना चाहिए जिसमें यह दिखाई देता है और सभी परिस्थितियां: शब्द साधारण अंग्रेजी शब्द हैं, जिनका सामान्य अर्थ है।”

*गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल बनाम एन'जेई*, (1961) 2 ए.ई.आर. 504 (6),

यह कहा गया था कि जेम्स, एलजे द्वारा 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा को संपूर्ण नहीं माना जाना था। उस मामले के तथ्य यह थे कि प्रतिवादी अंग्रेजी बार का सदस्य था, जिसे बैरिस्टर और गामबिया के सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर के रूप में अभ्यास करने के लिए स्वीकार किया गया था। जून, 1958 में, एक सिविल मुकदमे में निर्णय देने के दौरान, गाम्बिया के मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिवादी के कुछ आचरण की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता, गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल ने प्रतिवादी को एक प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ पेशेवर कदाचार के आरोपों की जांच करने और उस न्यायालय की सूची से उनका नाम हटाने के लिए कहा गया। 22, 1958, प्रतिवादी का नाम अदालत के रोल से हटा दिया गया और निर्देश दिया गया कि इसे अपनी सराय की बेंच के मास्टर्स को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। 5 जून, 1959 को, प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को पश्चिम अफ्रीकी अपील अदालत ने इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उप न्यायाधीश के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने तब परिषद में महामहिम से अपील करने की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, अटॉर्नी जनरल ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए महामहिम को एक याचिका दी, जिसे मंजूर कर लिया गया, लेकिन प्रतिवादी को प्रारंभिक बिंदु उठाने के लिए स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी कि अटॉर्नी जनरल के कहने पर कोई अपील नहीं की गई थी क्योंकि उन्हें पीड़ित व्यक्ति के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। उस बात के समर्थन में, रिलायंस को जेम्स, एल.जे. द्वारा 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा पर रखा गया था। *साइडबॉथम का मामला (सुप्रा) लॉर्ड डेनिंग ने प्रिवी काउंसिल के लिए बोलते हुए कहा: -*

"यदि इस परिभाषा को संपूर्ण माना जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि एकमात्र व्यक्ति जो पीड़ित हो सकता है वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक विवाद में एक पक्ष था, एक विवाद के बीच था, और उसके खिलाफ एक निर्णय दिया गया था। महान्यायवादी इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि, जैसा कि उनके लॉर्डशिप ने पहले ही उल्लेख किया है, इन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में पार्टियों के बीच कोई मुकदमा नहीं होता है, बल्कि केवल न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई की जाती है, पूर्व में या अटॉर्नी-जनरल या किसी अन्य के कहने पर, एक अपराधी व्यवसायी के खिलाफ।

लेकिन जेम्स, एल.जे. की परिभाषा को संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। लॉर्ड एशर, एमआर, ने *री रीड, बोवेन एंड कंपनी, एक्स पी ऑफिशियल रिसीवर (1887) 19 Q.B.D. 174 p. 178(7) में बताया*, 'पीड़ित व्यक्ति' शब्द व्यापक महत्व के हैं और इसे प्रतिबंधात्मक व्याख्या के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। बेशक, उनमें केवल एक व्यस्त व्यक्ति शामिल नहीं है जो उन चीजों में हस्तक्षेप कर रहा है जो उससे संबंधित नहीं हैं; लेकिन उनमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसकी वास्तविक शिकायत है क्योंकि एक आदेश दिया गया है जो प्रतिकूल रूप से किया गया है। उसके हितों को प्रभावित करता है। क्या अपीलकर्ता के पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त हित है? उनके लॉर्डशिप सोचते हैं कि उनके पास है। एक कॉलोनी में अटॉर्नी-जनरल सार्वजनिक हित के

संरक्षक के रूप में क्राउन का प्रतिनिधित्व करता है। यह उनका कर्तव्य है कि वह किसी बैरिस्टर या सॉलिसिटर के किसी भी कदाचार को न्यायाधीश के समक्ष लाएं जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त है। यह सच है कि यदि न्यायाधीश कदाचार के व्यवसायी को बरी कर देता है, तो अटॉर्नी जनरल के लिए कोई अपील खुली नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और दुखी नहीं हैं। लेकिन यदि न्यायाधीश चिकित्सक को कदाचार का दोषी पाता है, और अपील की अदालत इस आधार पर निर्णय को उलट देती है जो न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में जाता है या अन्यथा एक बिंदु है जिसमें जनता की राय का संबंध है, तो अटॉर्नी जनरल निर्णय से 'असंतुष्ट व्यक्ति' है और अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए महामहिम को उचित रूप से याचिका दे सकता है। यही कारण था कि उनके लॉर्डशिप ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता पश्चिम अफ्रीकी अपील अदालत के फैसले से 'व्यथित व्यक्ति' था।

थिरुवेंगडम बनाम मुथु चेट्टियार और एक और (ए.आई.आर. 1970 मद्रास 34) (8) में यह कहा गया था:-

एक व्यक्ति को पीड़ित कहा जा सकता है, अगर जनता के सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति के जीन के हित के अलावा, उस विषय-वस्तु में उसकी विशेष या विशेष रुचि हो सकती है, जिसे गलत तरीके से तय किया जाना चाहिए।

कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड III में, पृष्ठ 351 पर, पीड़ित पक्ष या व्यक्ति के संबंध में मूर्खतापूर्ण विवरण दिखाई देता है: -

"यह कहा गया है कि अभिव्यक्ति तकनीकी नहीं है और शब्दों को उनके स्वाभाविक अर्थ दिए जाने चाहिए, जो व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाई है, जो पीड़ित, उत्पीड़ित, घायल, परेशान या परेशान है, या जिसे दर्द या दुख दिया गया है। कानूनी स्वीकृति में, या कानूनी अर्थ में, और जब कानूनी उपायों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो शब्दों को पर्याप्त रूप से निश्चित अर्थ के रूप में माना जाता है जिसे संदर्भ और विषय के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। विषय वे अर्थ के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में हो सकते हैं जो कानूनी अर्थों में घायल है, या जो दूसरों की आक्रामकता से पीड़ित है। वाक्यांश 'पीड़ित पक्ष' और 'पीड़ित व्यक्ति' को 'प्रतिकूल पार्टी' के बराबर, समान या पर्यायवाची माना गया है।

“पीड़ित व्यक्ति” के इस प्रकार कई अर्थ हैं और प्रत्येक मामले में इस मामले का निर्णय लिया जाना है कि क्या कोई व्यक्ति, जो अपील दायर करने का दावा करता है, वह 'पीड़ित व्यक्ति' है या नहीं।

इब्राहिम अबूबकर और एक अन्य बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट इवैक्यूप्रॉपर्टी के कस्टोडियन जनरल, (1952 एस.सी.आर)(9)

ने इस बिंदु को विस्तार से निपटाया। उस मामले में, टेक चंद डोलवानी ने इवैक्यूप्रॉपर्टी के अतिरिक्त संरक्षक को जानकारी प्रदान की कि अबूबकर अब्दुल रहमान के पास काफी चल और अचल संपत्तियां हैं, जिसमें बॉम्बे में स्थित एक सिनेमा थिएटर, जिसे इम्पीरियल सिनेमा के नाम से जाना जाता है, और वह भारत के विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान चला गया था और सितंबर के महीने में कराची में बस गया था। 1947, जहां उन्होंने उस महीने में कुछ संपत्तियां खरीदीं। इस मामले में एक जांच की गई और 8 फरवरी, 1950 को यह आयोजित किया गया कि उक्त अबूबेकर एक विस्थापित नहीं था। अतिरिक्त संरक्षक ने उसी दिन अबूबेकर को एक और नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें कारण बताने के लिए कहा गया कि क्या उन्हें 1949 के विस्थापित संपत्ति (संशोधन) अध्यादेश संख्या 27 की धारा 19 के तहत इच्छुक विस्थापित घोषित नहीं किया जाना चाहिए, और 9 फरवरी, 1950 को उन्हें एक संशोधनकर्ता के रूप में निर्णय दिया। 31 मार्च, 1950 को टेक चंद डोलवानी ने 9 फरवरी, 1950 के आदेश के खिलाफ भारत के कस्टोडियन जनरल के पास अपील दायर की, जिसमें उक्त अबूबेकर को एक विस्थापित घोषित करने का आदेश देने की मांग की गई और कहा गया कि उन्हें पहला मुखबिर होने के नाते, उक्त सिनेमा आवंटित किया जाना चाहिए। एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि टेक चंद डोलवानी को अपील को प्राथमिकता देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह उस आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति नहीं थे जिसके खिलाफ अपील की गई थी। भारत के अभिरक्षक जनरल ने माना कि अपील 9 फरवरी, 1950 को अतिरिक्त संरक्षक द्वारा पारित आदेश से है, जिसमें उक्त अबूबेकर को प्रभावी रूप से एक इच्छुक विस्थापित घोषित किया गया था और मूल रूप से 8 फरवरी, 1950 को किए गए आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिसमें अबूबेकर की संपत्ति को विस्थापित संपत्ति के रूप में घोषित करने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि टेक चंद डोलवानी अपील में रुचि रखते थे और उन्हें इसे पसंद करने का अधिकार था। जब यह बिंदु

इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, इसे पृष्ठ 705 पर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया था -

"इस तर्क के उचित मूल्यांकन के लिए कि टेक चंद डोलवानी अध्यादेश की धारा 24 में उन शब्दों के अर्थ के भीतर 'पीड़ित व्यक्ति' नहीं हैं, अध्यादेश के तहत बनाए गए नियमों का उल्लेख करना आवश्यक है। नियम 5 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति जो जांच में रुचि रखने का दावा करता है या संपत्ति को विस्थापित संपत्ति के रूप में घोषित किया जा रहा है, संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर लिखित बयान के जवाब में एक लिखित बयान दर्ज कर सकता है, जिसमें दावा किया गया है कि संपत्ति को खाली संपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अभिरक्षक तब या तो उसी दिन या बाद के किसी भी दिन, जिस दिन सुनवाई स्थगित की जा सकती है, उन साक्ष्यों, यदि कोई हो, को सुनने के लिए आगे बढ़ेगा, जिन्हें कारण बताने की अपील करने वाला पक्ष प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा जो ऊपर उल्लिखित रुचि रखने का दावा करने वाला पक्ष जोड़ सकता है। अतिरिक्त संरक्षक के समक्ष कार्यवाही में, टेक चंद डोलवानी ने अबूबेकर के लिखित बयान का जवाब दाखिल किया और उनके द्वारा उठाए गए रुख के समर्थन में सबूत पेश किए कि अबूबेकर की संपत्ति खाली संपत्ति थी। इसके अलावा, टेक

चंद डोलवानी पहले मुखबिर थे जिन्होंने संबंधित संरक्षक के ध्यान में लाया कि अबूबेकर की संपत्ति खाली संपत्ति थी और पुनर्वास मंत्रालय के आदेश के मद्देनजर, वह एक पहला मुखबिर था, जो इस संपत्ति के आवंटन में पहले विचार करने का हकदार था, अतिरिक्त संरक्षक उसके द्वारा दी गई जानकारी की सच्चाई और वैधता पर उसे सुनने के लिए बाध्य था। जब किसी व्यक्ति को किसी निश्चित मामले में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार दिया जाता है और उसका विवाद नकारात्मक होता है, तो यह कहना कि वह आदेश से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, हमें बिल्कुल सही या उचित नहीं लगता है। वह निश्चित रूप से अपने तर्क को अस्वीकार करने वाले आदेश से व्यथित हैं। धारा 24 धारा 7 के तहत किए गए आदेश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है? अतिरिक्त अभिरक्षक द्वारा किया गया संपर्क फरवरी 1950 को अबूबेकर को विस्थापित नहीं करना धारा 7 के तहत एक आदेश के समान था और टेक चंद उस आदेश से व्यथित व्यक्ति थे। (जोर दिया गया)।

तर्क की समानता पर, यह कहा जा सकता है कि भूस्वामियों को कलेक्टर को सूचित करने का अधिकार था कि पट्टेदारों ने पट्टे की शर्तों को पूरा करने में चूक या चूक की थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके पक्ष में पट्टे का निर्धारण किया जाना चाहिए। जब भूस्वामियों के उस तर्क को अस्वीकार कर दिया गया, तो वे स्वाभाविक रूप से अपने विवाद के अस्वीकृति के खिलाफ व्यथित महसूस करते थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर पीड़ित व्यक्ति कहा जा सकता है। इसलिए, उनके पास कलेक्टर (एसडीओ (सी)), सिरसा के आदेश के खिलाफ आयुक्त के पास अपील करने का अधिकार था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पट्टों को समाप्त करने से इनकार कर दिया गया था, हालांकि एक निष्कर्ष दिया गया था कि उन्होंने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया था। यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पट्टे रद्द कर दिए गए थे, तो भूस्वामी कलेक्टर से अनुरोध कर सकते हैं कि वे किसी भी अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भूमि पट्टे पर न दें, बल्कि उन्हें इसे बहाल करें। कलेक्टर ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया होगा या नहीं, लेकिन भूमि के मालिकों के रूप में कलेक्टर से अनुरोध करने में उनकी पर्याप्त रुचि थी। भूमि में उनके मालिकाना अधिकार मौजूद थे और केवल अस्थायी रूप से भूमि पर कब्जा करने का अधिकार कलेक्टर द्वारा अधिग्रहण द्वारा लिया गया था।

श्री एन एल ढींगरा ने तब तर्क दिया था कि भूस्वामियों को 20 वर्ष की समाप्ति से पहले भूमि को बहाल करने का कोई अधिकार नहीं है, जो पट्टे की अधिकतम अवधि है और उन्होंने इस तथ्य से अपने तर्क का समर्थन करने का प्रयास किया है कि धारा 7 में, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, शब्द थे: -

"जहां धारा 3 के तहत कलेक्टर द्वारा कब्जा की गई कोई भी भूमि पट्टे की समाप्ति या इसकी पूर्व समाप्ति पर है, उसे मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए। .....

और यह कि "या इसकी पूर्व समाप्ति" शब्द को पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 1951, (1951 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) द्वारा हटा दिया गया था, जिसमें से विधायिका का इरादा स्पष्ट था कि भूस्वामी को 20 साल की समाप्ति के बाद ही भूमि वापस मिलनी चाहिए, न कि पहले। मुझे खेद है कि मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हूँ। "या इसकी पूर्व समाप्ति" शब्द धारा 7 से हटा दिए गए थे क्योंकि उसी संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम से धारा 6 को हटा दिया गया था। धारा 6 की चूक के परिणामस्वरूप, "या इसकी पूर्व समाप्ति" शब्द निरर्थक हो गए। संशोधित रूप में धारा 6 को फिर से अधिनियम में शामिल किया गया



पंजाब भूमि उपयोग (संशोधन) अधिनियम (1957 का पंजाब अधिनियम \* संख्या 24) द्वारा निम्नानुसार है:-

6. कतिपय मामलों में पट्टा निर्धारित करने की कलेक्टर की शक्ति-

(एक) यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 5 के तहत भूमि पट्टे पर दी गई है, उसके किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर को उसके खिलाफ किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, पट्टे का निर्धारण करने और भूमि का कब्जा लेने की शक्ति होगी।

(दो) जहां कलेक्टर द्वारा पट्टा निर्धारित किया गया है, पट्टेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

इस धारा को 1971 के पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम संख्या 35 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और प्रतिस्थापन 29 जुलाई, 1957 से प्रभावी होना था। वह तारीख जिस पर 1957 के पंजाब अधिनियम संख्या 24 द्वारा धारा 6 को जोड़ा गया था। इस खंड को 29 जुलाई से पढ़ा जाना है। 1957, निम्नानुसार :-

"6. कतिपय मामलों में पट्टा निर्धारित करने की कलेक्टर की शक्ति

(एक) यदि कोई किरायेदार अपनी किरायेदारी के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कलेक्टर के पास पट्टे का निर्धारण करने और किरायेदार को कारण बताने के लिए उचित अवसर देने के बाद भूमि का कब्जा लेने की शक्ति होगी कि उसका पट्टा क्यों निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए और भूमि का कब्जा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।

(21) जहां उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर द्वारा पट्टा निर्धारित किया गया है, किरायेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

(तीन) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के विभिन्न प्रावधानों में सन्निहित सिद्धांत इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे।

(चार) किसी भी सिविल या राजस्व अदालत के पास पट्टे के निर्धारण या किरायेदार के निष्कासन के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 7 में "पट्टे की समाप्ति पर" शब्द वास्तव में उस चरण को दर्शाता है जब भूमि किसी भी व्यक्ति की वैधता के अधीन नहीं रहती है, चाहे पट्टे की समाप्ति या पट्टेदार द्वारा परित्याग या किसी अन्य तरीके से। जब

पट्टेदार का पट्टा पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारित किया जाता है क्योंकि डिफॉल्ट प्रतिबद्ध होने के कारण, पट्टा समाप्त हो जाता है और समाप्त हो जाता है। उसकी लीज खत्म होने के बाद इसे जारी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद, कलेक्टर द्वारा किसी और के पक्ष में एक और पट्टा बनाया जा सकता है, यदि वह ऐसा सोचता है या वह भूमि मालिक को बहाल कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि वह उसी पर खेती करने की स्थिति में है। इसलिए, धारा 7 से "या इसकी पूर्व समाप्ति" शब्दों को हटाने का मतलब यह नहीं है कि भूस्वामी को 20 साल की अवधि की समाप्ति से पहले अपनी भूमि की बहाली के लिए कलेक्टर से प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही पट्टेदार के पक्ष में पट्टा कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन मामलों में भूस्वामियों को भूमि के मालिक के रूप में भूमि में रुचि थी और कलेक्टर को सूचित करने के उनके रास्ते में कोई रोक नहीं थी कि पट्टे के निर्धारण के लिए आधार मौजूद थे और यदि उनके विवाद को स्वीकार कर लिया गया था और पट्टे निर्धारित किए गए थे, तो उनके पक्ष में भूमि की बहाली के लिए एक आदेश पारित किया जा सकता है। चूंकि याचिकाकर्ताओं के पट्टों के निर्धारण के लिए उनकी दलील, यहां तक कि उनके द्वारा चूक किए जाने पर भी, अस्वीकार कर दी गई थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से असंतुष्ट व्यक्ति थे जो अपील दायर कर सकते थे। इसलिए, आयुक्त के समक्ष इन मामलों में भूस्वामियों द्वारा दायर अपील सक्षम थी। मामलों को अब एकल न्यायाधीश के समक्ष गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए तय किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रांशु जैन  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,  
गुरुग्राम, हरियाणा